



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 17, 1992 (अश्विन 25, 1914)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1992 (ASVINA 25, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के	पृष्ठ
	मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से अखिल गठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	805
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	1105
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निरीक्षक और मजलेखा-परिगणक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	13
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खण्ड 2—नोटिफ़ेड कार्यालय द्वारा जारी की गई नोटिफ़ेडों और डिआइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिफ़ेड	1799
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आदेशों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III—खण्ड 4—नियम अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विनियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिफ़ेड शामिल हैं	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिना तथा रिपोर्ट	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिफ़ेड	1011
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	भाग V—प्रदेशों और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को रवाना बाना अनुपूरक	1251
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं		3463
		159

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	805	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1105	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1011
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1799	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1251
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3463
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	159
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1992

सं० ए-11019/2/86-एडी-1—यह अधिसूचना इस सचिवालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 13 जुलाई, 1989 के संदर्भ में है जिसमें समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी।

सरकार ने समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड का कार्यकाल 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निश्चय किया है जिसकी संरचना इस प्रकार है :—

- | | |
|---|--------|
| 1. सचिव, महामागर विभाग | सभापति |
| 2. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | सदस्य |
| 3. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | सदस्य |
| 4. सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय | सदस्य |
| 5. सचिव, खाद्य संवर्धन उद्योग मंत्रालय | सदस्य |
| 6. सचिव, खान विभाग | सदस्य |
| 7. सचिव, पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय | सदस्य |
| 8. रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार | सदस्य |
| 9. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | सदस्य |
| 10. महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग | सदस्य |
| 11. प्रो० बी० एल० के० सोमायाजुलु, वैज्ञानिक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद। | सदस्य |
| 12. प्रो० आर० नरसिम्हा, निदेशक, राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला बंगलूर। | सदस्य |

संजीव मिश्रा,
संयुक्त सचिव

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 सितम्बर, 1992

सं० 27/5/92-सी० एन०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) खंड(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य

विभाग के सबे श्री श्रीराम, निरीक्षण अधिकारी, एवं मनी राम, सहायक निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

आर० एन० वासुधानी,
अवर सचिव

सं० 27/5/92-सी० एन०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री पी० के० बंसल, उप निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

आर० एन० वासुधानी,
अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 1992

संकल्प

सं० 24-3/89-सी० ए० 2—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 24-3/89-सी० ए० 2, दिनांक 7 अप्रैल, 1991 के द्वारा गठित भारतीय पदमन विकास परिषद को तत्काल से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद का गठन निम्न प्रकार होगा :—

- | | |
|--------------|--|
| 1. अध्यक्ष | एक गैर-सरकारी सदस्य जिसे भारत सरकार नामजद करेगी। |
| 2. उपाध्यक्ष | कृषि अल्पना, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली। |
| 3. क. सदस्य | तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जिन्हें संसदीय कार्य विभाग नामजद करेगा। |

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

निम्न प्रत्येक राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी :

- (1). आन्ध्र प्रदेश
- (2) असम

	(3) बिहार (4) मेघालय (5) उड़ीसा (6) त्रिपुरा (7) उत्तर प्रदेश (8) पश्चिम बंगाल	ज. समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले अन्य व्यक्ति । सरकार	
(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	(क) योजना आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य । (ख) संयुक्त सचिव (ग्रामिण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नयी दिल्ली या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति । (ग) पटसन आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय, कलकत्ता । (घ) निदेशक, पटसन, कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरगुर, पश्चिम बंगाल । (ङ) निदेशक, पटसन औद्योगिकी प्रयोगशाला, टी-12, गेजेट पार्क, कलकत्ता । (च) गृहनिर्देशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति । (छ) प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता । (ज) संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फगलें) कृषि तथा सहकारिता विभाग । (झ) नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।	4. सदस्य सचिव निदेशक, पटसन विकास निदेशालय, कलकत्ता । 5 प्रेरक— (ये व्यक्ति परिषद के सदस्य नहीं होंगे परन्तु उन्हें परिषद के विचार-विमर्श में सहभागिता के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाएगा) । 1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उनका प्रतिनिधि । 2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग । 3. अर्थ और गांक्षिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि । 4. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग या उनका प्रतिनिधि । 5. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि । 6. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, नई दिल्ली । 7. वनस्पति रक्षण सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फरीदाबाद । 8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि । 9. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग या उनका प्रतिनिधि ।	
[(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि	(क) निम्न पटसन उत्पादक राज्यों में प्रत्येक से पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि, जिसे संबंधित राज्य सरकार नामजद करेगी :— (1) आन्ध्र प्रदेश (2) असम (3) बिहार (4) मेघालय (5) उड़ीसा (6) उत्तर प्रदेश (7) त्रिपुरा (8) पश्चिम बंगाल (ख) पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार नामजद करेगी ।	2. परिषद् सलाहकार निगाह के रूप में कार्य करेगी तथा उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :— (क) पटसन, मेस्ता तथा अन्य रेशे वाली फसलों (कपास को छोड़कर) के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम पर विचार करना । समय-समय पर उनकी प्रगति की मंथीक्षा करना तथा पटसन और मेस्ता का उत्पादन बढ़ाने के उपाय सुझाना; (ख) पटसन के उत्पादन और विपणन और पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों पर सरकार को सलाह देना; (ग) देशी तथा निर्यात मंडियों में पटसन की विभिन्न किस्मों की मांग के संबंध में विचार करना तथा तबनुसार पटसन उत्पादन के कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन हेतु सुझाव देना; (घ) पटसन और मेस्ता के बारे में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष जरूरतों पर विचार करना और उनकी पूर्ति के लिए उचित उपायों का सुझाव देना,	
ङ उद्योग का प्रतिनिधि	भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि ।		
ज. व्यापार का प्रतिनिधि	जूट डीलर्स एसोसिएशन कलकत्ता का एक प्रतिनिधि ।		
छ. कर्मचारियों का प्रतिनिधि	(1) फार्म में लगे कर्मचारी—एक (2) फेक्ट्री में लगे कर्मचारी—एक		

(क) पटसन और मेस्ता से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना और पटसन तथा मेस्ता की ब्यालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सलाह देना; और

(ख) सरकार को ऐसे अन्य सम्बद्ध विषयों पर सलाह देना, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं।

3. परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समितियाँ, तकनीकी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ नियुक्त करके तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष उद्देश्यों हेतु कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष रुचि रखने वालों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

4. परिषद पटसन उगाए जाने वाले क्षेत्रों तथा पटसन के व्यापार एवं उद्योग से सम्बद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय-समय पर बैठकें करेगी तथा भारत सरकार को सुझाव देगी।

5. परिषद उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि भारत सरकार के संकल्प द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद के लिए मनोनीत होने की तारीख से 3 वर्ष तक होगा, बशर्ते कि भारत सरकार अपने विशेष आदेश द्वारा उसे घटा या बढ़ा न दे।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए जाने वाले सदस्यों की संख्या उनके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

रवि मोहू सेठी,
संयुक्त सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1992

संकल्प

सं० 11011/5/90-हिन्दी—श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव, लेखक एवं पत्रकार को विद्युत मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है और श्रीमती बी० एस० शांताबाई, प्रधान सचिव, कर्माटक महिला हिन्दी सेवा समिति, 178 मैन रोड, कामराजपेट, बंगलौर-560018 को गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 25 जून, 1992 के का० शा सं० 11/20015/62-89-रा० भा० (क-2) के माध्यम से श्रीमती एस० महालक्ष्मी जिनका नाम तत्कालीन विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा भोत मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1992 के संकल्प सं० 11011/5/90-हिन्दी की क्रम सं० 15 पर दिया गया है के स्थान पर नामित किया गया है।

2. उपर्युक्त पैरा-1 में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि तत्कालीन विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1992 के संकल्प सं० 11011/5/90-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए विद्युत मंत्रालय की

हिन्दी सलाहकार समिति के संघटन में तत्काल निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :—

(1) श्रीमती कामता मुक्ता, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के नाम के बाद क्रम संख्या 12-क पर श्री हरिहर लाल [श्रीवास्तव, लेखक एवं पत्रकार, के०-56/31, औसानगंज, वाराणसी का नाम जोड़ा जाए और

(2) श्रीमती एस० महालक्ष्मी के स्थान पर श्रीमती बी० एस० शांताबाई, प्रधान सचिव, कर्माटक महिला हिन्दी सेवा समिति, 178-4, मैन रोड, कामराजपेट, बंगलौर-560018 का नाम पढ़ा जाए।

(3) इन सदस्यों की कार्य अवधि फरवरी, 1995 तक होगी। पैरा-2, 4 तथा 5 में निहित अन्य शर्तें एवं निर्बंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० के० दीवान,
संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर, 1992

संकल्प

सं० 14/1/92-हिन्दी—जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के सम्बन्ध में 4 अगस्त, 1992 के समसंख्यक संकल्प में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

संकल्प के पैरा 1 में क्रम संख्या 15 के नीचे क्रम संख्या 16 के रूप में निम्नलिखित सदस्य का नाम शामिल किया जाए और इससे आगे की क्रम संख्या को तदनुसार पढ़ा जाए :

16. " श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव, के० 56/31 सस्य औसानगंज, वाराणसी"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अभय प्रकाश,
संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 8th September 1992

No. A-11019/2/86-Ad I.—Reference this Secretariat's Resolution of even number dated 13th July, 1989, notifying the extension of the term of the Ocean Science and Technology Board.

The Government have decided to extend the term of the Ocean Science and Technology Board for a further period of one year with effect from 1-4-1992 to 31-3-93 with the following composition :—

Chairman

1. Secretary, Department of Ocean Development

Members

2. Secretary, Department of Science & Technology
3. Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas
4. Secretary, Ministry of Surface Transport
5. Secretary, Ministry of Food Processing Industries
6. Secretary, Department of Mines
7. Secretary, Ministry of Environment & Forests
8. Scientific Adviser to Raksha Mantri
9. Director General, Indian Council of Agricultural Research
10. Director General, Council for Scientific & Industrial Research and Secretary, Department of Scientific & Industrial Research
11. Prof. B. L. K. Somayajulu, Scientist, Physical Research Laboratory, Ahmedabad
12. Prof. R. Narasimha, Director, National Aeronautical Laboratory, Bangalore.

SANJIV MISRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 16th September 1992

No. 27/5/92-CL.II—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Mani Ram, A.O. and Sh. Shri Ram, I.O., in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI, Under Secy.

No. 27/5/92-CL.II—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri P. K. Bansal, Dy. Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 14th September 1992

RESOLUTION

No. 24-3/89-C.A.II—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Jute Development Council constituted vide this Ministry's Resolution No. 24-3/89-C.A.II. dated the 27th April, 1991. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE CHAIRMAN

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

III. MEMBERS

A. MEMBERS OF PARLIAMENT :

Three Members of Parliament (Two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.

B. REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS :

One representative from each of the following States in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

- (i) Andhra Pradesh
- (ii) Assam
- (iii) Bihar
- (iv) Meghalaya
- (v) Orissa
- (vi) Tripura
- (vii) Uttar Pradesh
- (viii) West Bengal

C. REPRESENTATIVE OF CENTRAL GOVERNMENT :

- a. Adviser (Agriculture), Planning Commission, New Delhi.
- b. Joint Secretary (Extension), Department of Agri. & Cooperation or his nominee.
- c. Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Calcutta.
- d. Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.
- e. Director, Jute Agricultural Research Institute (ICAR), Barrackpore (W. Bengal).
- f. Director, Jute Technological Research Laboratory, Calcutta.
- g. Managing Director, Jute Corporation of India, Calcutta.
- h. Joint Commissioner dealing with the Jute in the Department of Agriculture & Cooperation.
- i. A representative of the Ministry of Civil Supplies.

D. REPRESENTATIVE OF GROWERS :

One Grower's representatives to be nominated by the respective State Governments from the major Jute/Mesta growing States as follows :—

(No. of representative)

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Andhra Pradesh | One |
| 2. Assam | One |
| 3. Bihar | One |
| 4. Meghalaya | One |
| 5. Orissa | One |
| 6. Tripura | One |
| 7. Uttar Pradesh | One |
| 8. West Bengal | One |

E. REPRESENTATIVE OF TRADE :

One representative of the Jute Dealer's Association.

F. REPRESENTATIVE OF INDUSTRY :

One representative of the Indian Jute Mills Association, Calcutta.

G. REPRESENTATIVE OF WORKERS :

- (i) Workers engaged in Farms—One
- (ii) Workers engaged in Factory—One

H. SUCH ADDITIONAL PERSONS AS MAY FROM TIME TO TIME BE NOMINATED BY THE GOVERNMENT OF INDIA.**IV. MEMBER SECRETARY :**

The Director,
Directorate of Jute Development,
234/4, Acharya Jagdish Bose Road,
Nizam Palace Campus, CALCUTTA-700020.

V. OBSERVERS :

Who would not be Members of the Council, but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations)

1. Chairman, State Trading Corporation or his nominee/representative.
2. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Rural Development or his representative.
3. Financial Adviser, Department of Agriculture & Cooperation.
4. Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agri. & Cooperation or his nominee.
5. Plant Protection Adviser to the Govt. of India, Department of Agriculture & Cooperation or his nominee.
6. Chairman, Agricultural Costs and Prices Commission or his nominee/representative.
7. Managing Director, National Seeds Corporation, New Delhi.
8. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
9. A representative of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd., New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

- (i) To consider development programme in the Central and State Sector in respect of Jute, Mesta and other fibre crops (excluding Cotton) thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of jute and mesta;
- (ii) To consider problems relating to the production and marketing of jute and remunerative prices to jute growers and advise Government in these matters.
- (iii) To consider demands for different varieties of jute in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programme accordingly;
- (iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of jute and mesta production and suggest suitable measures for meeting the same;
- (v) To facilitate coordination between Research and Development programmes relating to jute and mesta to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of jute and mesta; and

- (vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and Ad hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which jute is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by specific order of the Govt. of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. M. SETHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th September 1992

RESOLUTION

No. 11011/5/90-Hindi.—Shri Harihar Lal Srivastav, Writer and journalist, has been nominated as an additional non-official member of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Power and Smt. B. S. Shantabai, Pradhan Sachiv, Karnatak Mahila Hindi Sewa Samiti, 1784, Main Road, Chamrajpet, Bangalore-560 018, has been nominated vide Ministry of Home Affairs (Department of Official Language), O.M. No. 11/20015/62-89-OL (A-2), dated 25-6-1992 in place of Smt. S. Mahalakshamma, appearing at Sl. No. 15 of the erstwhile Ministry of Power and Non-conventional Energy Sources Resolution No. 11011/5/90-Hindi, dated the 26th February, 1992.

2. In view of the position explained in para 1 above, it has been decided by the Government of India, in partial modification of the erstwhile Ministry of Power & Non-conventional Energy Sources Resolution No. 11011/5 90-Hindi, dated the 26th February, 1992, that the following changes in the composition of Hindi Advisory Committee of the Ministry of Power, be carried out with immediate effect :—

- (i) The name of Shri Harihar Lal Srivastav, writer and Journalist, K-56/31, Oshin Ganj, Varanasi, be added at Sl. No. 12-A, after the name of Smt. Kanta Shukla, Lucknow (UP) and that
- (ii) the name of Smt. B. S. Shantabai, Pradhan Sachiv, Karnatak Mahila Hindi Sewa Samiti, 178-4, Main Road, Chamrajpet, Bangalore-560 018, in place of Smt. S. Mahalakshamma.

3. The terms of these Members shall be upto 25th February, 1995. The other terms and conditions, contained in para II, IV and V shall remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to all Members of the Committee, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Planning Commission, Raj Bhasha Vibhag, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. DEWAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th September 1992

RESOLUTION

No. 14/1/92-Hindi.—The following amendments are hereby made in the Resolution of even number dated 4th August,

1992 regarding constitution of Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Water Resources :

In Para 1 of the Resolution, below Sl. No. 15, the name of the undermentioned Member be included at Sl. No. 16 and the subsequent Sl. Nos. may be read accordingly :

"16. Shri Harihar Lal Srivastava, K 56/31, Osanganj, Varanasi."—Member

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Departments of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ABHAY PRAKASH, Jt. Secy.